



The legend of the white gibbon of Tinting...

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

# राष्ट्रदूत

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

Buja took the stone, woke up from his dream and walked away, and the white gibbon seemed to have disappeared. This is how the ridge that Buja went hunting is named as Tinting Empeliau

A kid's school project turned into a national story

## ‘3 8 9 7 एसबीआई बैंक खातों की निजी जानकारी डार्क वेब पर एक्सपोज़ हुई’

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया कि यह सब एक सायबर अटैक की वजह से हुआ है

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बुधवार को साइबर हमले की जानकारी दी। इस अटैक की वजह से 3,897 ग्राहकों के रिकॉर्ड से जुड़ी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी डार्क वेब पर उजागर हो गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह खबर दी है। बैंक के अनुसार, शुरुआती आकलन में पता चला कि लीक हुए डेटा में ग्राहकों के नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल पते, आवासीय पते, ब्रांड और ग्राहक पहचान संबंधी विवरण तथा ऋण से जुड़े रिकॉर्ड शामिल थे। एसबीआई ने कहा कि उसने डेटा लीक की प्रकृति और उसके दायरे का पता लगाने तथा पूरे मामले की जांच

- बैंक की प्रारम्भिक जाँच में पता चला है कि खाता धारकों के नाम, मोबाइल नंबर, आधार, जन्म तारीख, ईमेल आईडी, घर का पता, ब्रांड व ग्राहक पहचान संबंधी विवरण डार्क वेब पर उजागर हो गए हैं। बैंक ने पूरी जाँच के लिए एक स्वतंत्र सायबर सुरक्षा एजेंसी की सुविधाएं ली हैं।
- बैंक ने कहा कि इस घटना से अभी तक बैंक के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है, पर स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रहा है।

के लिए एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी नियुक्त की है। बैंक ने यह भी कहा कि इस घटना से उसके मुख्य कारोबारी कामकाज, वित्तीय प्रदर्शन या कारोबार की निरंतरता पर कोई बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है।

ग्राहकों तथा बैंक के लिए संभावित जोखिमों की जांच की जाएगी। बैंक ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नज़र रख रहा है और 3,897 ग्राहकों के चिन्हित रिकॉर्ड से जुड़े मामले की जांच जारी रहने के दौरान लागू नियामकीय नियमों के अनुसार उचित कदम उठाएगा। यह डेटा लीक ऐसे समय सामने आया है, जब बैंकिंग क्षेत्र में नियामकीय निगरानी बढ़ रही है। भारत का बैंकिंग नियामक पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने वाले साइबर खतरों में वृद्धि के बीच बैंकों से अपनी साइबर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहता रहा है। जुलाई में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी डेटा लीक की पुष्टि की थी, जिसमें एक टेराबाइट ग्राहक डेटा उजागर हुआ था।

लिखित माफीनामे के बाद सीजेपी नेताओं को जमानत मिली

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। कॉंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सौरव दास और आशुतोष रांका के लिए बुधवार का दिन बेहद अहम रहा। बीते सात दिनों से तिहाड़ जेल में बंद दोनों सीजेपी नेताओं को जमानत मिल गई। सौरव दास और आशुतोष रांका से लिखित में माफीनामा और शपथ पत्र

- सौरव दास व आशुतोष रांका सात दिन से तिहाड़ जेल में बंद थे।

लेने के बाद इनको जमानत पर छोड़ा गया है। करीब डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई के बाद स्पेशल एंजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और फिर दोनों को जमानत का फैसला सुनाया। इसके लिए कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच सीजेपी के दोनों सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को पेशी के लिए मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एंजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लाया गया था। इन दोनों की इस कोर्ट में यह तीसरी पेशी है। पिछली दो पेशियों में दोनों को जमानत खारिज कर दी गई थी। यहां तीसरी बार बेल बॉन्ड भरवाने के बाद सुनवाई शुरू हो गई है। आज अगर दोनों के जमानती से कोर्ट संतुष्ट हो जाएगी, तब इन्हें जमानत पर छोड़ा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## एप्सटीन फाइल्स के फोटो मीडिया में आए, हरदीप पुरी फिर से विवादों में

अमेरिका के न्याय विभाग ने एप्सटीन फाइल्स की कुछ और तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें हरदीप पुरी, कुख्यात यौन अपराधी जैफ्री एप्सटीन के साथ अकेले बैठे दिख रहे हैं

**-श्रीनंद झा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी एप्सटीन फाइलों की तस्वीरों ने भारत में नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यौन अपराधों में दोषी ठहराए गए दिवंगत जैफ्री एप्सटीन के साथ एक मेज के आमने-सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस साल की शुरुआत में जारी किए गए डेटासेट-9 का हिस्सा हैं और मंगलवार से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में दोनों व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेताओं ने इन

- गौरतलब है कि पूर्व में जब हरदीप पुरी का नाम एप्सटीन फाइल्स में आया था, तब उन्होंने दावा किया था कि वे कभी एप्सटीन से अकेले नहीं मिले। उन्होंने कहा था, सिर्फ तीन-चार बार मुलाकात हुई थी, तब मैं एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल था।
- अमेरिका द्वारा हाल ही में जारी तस्वीरों को देखकर विपक्ष ने पुरी पर कटाक्ष किया, क्या इन तस्वीरों में प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य अदृश्य हो गए हैं?

तस्वीरों को लेकर पुरी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये तस्वीरें फरवरी 2026 में पुरी के दिए गए बयानों के विपरीत हैं। उस समय पुरी ने कहा था कि उनकी एप्सटीन से “तीन या ज्यादा से ज्यादा चार बार” मुलाकात हुई थी। उनके मुताबिक, ये मुलाकातें उनके तत्कालीन बॉस टेजें रोड-लार्सन के

नेतृत्व वाले “इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट” या इसके “इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म” के प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में हुई थीं। रोड-लार्सन एप्सटीन को जानते थे। पुरी ने जोर देकर कहा था कि ये मुलाकातें पूरी तरह से प्रॉफेशनल थीं, जो बहुपक्षवाद या ‘मेक इन इंडिया’ तथा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## सर्दी आने से पहले ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई

बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-वन लागू किया गया है

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण और धुंध बढ़ने की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। इस सीजन में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर) में ग्रेडेड रैस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले चरण के तहत, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू किए गए हैं। जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स-एक्यूआई) 201 से 300 के बीच पहुंच जाता है, तब ग्रेप-1 लागू किया जाता है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेटेमेंट-सीएक्यूएम) ने बताया कि बुधवार दोपहर दो बजे दिल्ली का एक्यूआई 244 दर्ज किया गया।

पाकिस्तान के ननकाना साहिब दर्शन के लिये श्रद्धालू जत्था 22 नवम्बर को जायेगा

चंडीगढ़, 21 अक्टूबर। प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पाकिस्तान स्थित उनके जन्मस्थान गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब

- दस दिवसीय धार्मिक यात्रा के लिये 1828 सिख श्रद्धालुओं ने पाकिस्तान उच्चयोग में पासपोर्ट जमा कराया।

में मनाने के लिए भारत से सिख श्रद्धालुओं का जत्था 22 नवंबर को रवाना होगा। 10 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के पासपोर्ट बुधवार को दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में जमा करवाए गए। जत्थे में पंजाब समेत, भारत के अलग-अलग राज्यों से सिख श्रद्धालू शामिल होंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ग्रेप-वन यानि ग्रेडेड ए रैस्पॉन्स एक्शन प्लान तब लागू किया जाता है, जब ए.क्यू.आई. 201 से 300 के बीच होता है।
- दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हम 11 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू कर रहे हैं हमारी योजना धूल-मिट्टी पर रोक लगाने के साथ ई-वाहनों को प्रमोट करने की है।

सीएक्यूएम ने अपने बयान में कहा, “20 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 179 यानी ‘मध्यम’ श्रेणी में था। इसमें तेज वृद्धि हुई और 21 अक्टूबर, 2026 को दोपहर दो बजे एक्यूआई 244 पर पहुंच गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में भी वायु

गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में बने रहने की संभावना है।”

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि कई वर्षों में यह पहली बार है, जब मौसम के अपेक्षाकृत बाद के चरण में ग्रेप लागू किया गया है।

उन्होंने कहा, “दिल्ली कई वर्षों से गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। पिछली सरकार बहाने बनाती रही, जबकि हमने प्रदूषण से निपटने के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फ्रांस से लौटे भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका, 50 हजार कस्टम ड्यूटी लगाई

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस दौर से लौटते ही बवाल मच गया। दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया कि फ्रांस से लौटते समय भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब तीन

- आप पार्टी ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री को तीन घंटे हवाई अड्डे पर रोका गया।

घंटे तक रोके रखा और 50 हजार रुपये का चालान किया गया। आप नेता सीरभ भारद्वाज और बलतेज पन्नू ने इसे लेकर केन्द्र पर निशाना साधा।

सीरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सीएम मान को हवाई अड्डे पर करीब 3 घंटे तक रोका गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने राज्य के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जब 2 9 जुलाई को दो चुनाव आयुक्तों ने असामान्य कदम उठाया!

चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों ने 29 जुलाई को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बजाय सीधे कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखी थी

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। 29 जुलाई को भारत के तीन चुनाव आयुक्तों में से दो ने एक असामान्य कदम उठाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखने के बजाय, कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। “इंडिया टुडे” को विशेष रूप से प्राप्त सूचना के अधिकार (राइट टु इन्फॉर्मेशन-आरटीआई) के जवाब से पता चला है कि सेवा तीर्थ परिसर में इन पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई। ज्ञातव्य है कि सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तथा कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं। 19 अक्टूबर को जारी जवाब, 24 सितंबर को दाखिल आरटीआई आवेदन के संबंध में दिया गया है। इसमें पुष्टि की गई है कि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से 29 जुलाई को लिखे गए दोनों पत्र कैबिनेट सचिवालय को प्राप्त हुए थे।

- यह खुलासा एक आरटीआई के तहत हुआ है, इसका जवाब इंडिया टुडे के पास उपलब्ध है।
- कैबिनेट सचिवालय ने 19 अक्टूबर को भेजे जवाब में माना है कि उसे चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा 29 जुलाई को भेजे गए दो अलग-अलग पत्र मिले थे।
- कैबिनेट सचिवालय के जवाब में यह नहीं बताया गया कि, पत्रों में क्या लिखा था। सचिवालय ने दोनों पत्र, जवाब व फाइल पर लिखी नोटिंग को सार्वजनिक नहीं किया है, इसके लिए 28 रूपए का शुल्क मांगा गया है।

दोनों पत्र 30 जुलाई को दर्ज किए गए। इसके बाद 5 अगस्त तक कैबिनेट सचिव ने इन्हें कार्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को भेज दिया। लेकिन इन पत्रों में क्या लिखा गया था, इसका खुलासा नहीं किया गया है। सचिवालय ने सभी 14 पृष्ठ देने पर

एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस ऑर्डर पर आपत्ति जताई थी और इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। बाद में कार्य-आवंटन के इस नए आदेश को रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि इन बदलावों से मतदाता सूचियों के आईटी ढांचे की निगरानी की एक परत प्रभावी रूप से हटा दी गई थी। चुनाव आयुक्तों ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये परिवर्तन उनकी जानकारी के बिना किए गए थे। समाचार पत्र ने इस कदम को “सामान्य परंपरा से पूर्णतः हटना” (अ रैडिकल डिचार्जर प्रॉम द नॉर्म) बताया था।

इस बीच, एक अन्य समाचार पत्र ने मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से पहले खबर दी थी कि पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बजाय, एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त से संबंधित था। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक्सप्रेसवे पर अन्नपूर्णा रसोई खोलने पर विचार

जयपुर, 21 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के एक्सप्रेसवेज पर दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालकों के लिए आवश्यक सुविधाएं रियायती दरों पर

- पंचायती राज विभाग ने एनएचएआई को प्रस्ताव भेजने के लिए पत्र लिखा।

उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग ने एक्सप्रेसवेज पर स्थित रेस्ट एरियाज में अन्नपूर्णा रसोइयों (ग्रामीण) के खोले जाने की संभावना का परीक्षण कर एन.एच.ए.आई. के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्ताव भिजवाने के लिए पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 6-ईं आधारित कार्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बहस का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रभाकर ने सोशल मीडिया पर अपनी भागीदारी की घोषणा करते हुए लिखा, “हर गली में जंतर-मंतर। शक्रवार, 23 अक्टूबर, 2026, लोकतंत्र की बहाली के लिए जन मार्च। आइए, इस चुनौती का सामना करें।” इस विरोध प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा और लेखक तुषार गांधी सहित कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। गठबंधन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के दलों से भी इसमें भाग लेने की अपील की है, हालांकि उनकी भागीदारी की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहराई से जुड़े परिवार में भी राजनीतिक विचार अलग-अलग हो सकते हैं। साथ ही, यह “एन्टी एसआईआर” अभियान को एक नया सार्वजनिक चेहरा भी देता है, ऐसे समय में, जब विपक्षी दल और नागरिक समाज के समूह चुनावी पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही पर

की मांग कर रहा है।

इसमें प्रभाकर की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे न केवल नरेन्द्र मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं, बल्कि इसलिए भी, कि उनकी पत्नी इसी सरकार की सबसे प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं।

प्रभाकर, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज, वरिष्ठ अधिकृता प्रशांत भूषण और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के साथ शामिल होंगे। यह अभियान मतदाता सूची में संशोधन की इस प्रक्रिया को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे